इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486 र

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 10, शक 1938

गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

क्र. एफ. 35-112-2015-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्तता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से तीन माह की अविध के लिए प्रतिषेध करती है.

## अनुसूची

दुग्ध संकलन, संसाधन एवं वितरण सेवाओं के निर्बाध संसाधन हेतु नियुक्त किए गए (अधिकारी/कर्मचारी) कर्मी (पर्सोनल).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

क्र. एफ. 35-112-2015-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, उपसचिव.

### Bhopal, the 1st December 2016

F.No.35-112-2015-II-C-1.— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashvak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 1st December, 2016 for a period of three months.

#### **SCHEDULE**

" Personnel appointed for all the works related to the Distribution of Milk live stock and Veterinary and Animal Hosbandry and Poultry Services.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, B. S. KÜLESH, Dy. Secy.